एक आयोग की दिनांक 12.8.1994 को स्थापना कर दी गई है जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी कार्य का निष्पादन करेगा:–

(1) एक समयबद्ध कार्य योजना के अधीन सफाई कर्मचारियों के लिए अवसरों, सुविधाओं तथा दर्जे की असमानता के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य योजना पर केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

(2) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन तथा अध्ययन और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को बेहतर समन्वय तथा ऐसे कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(3) विशिष्ट शिकायतों का अन्वेषण तथा गैर कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर अपनी तरफ से सूचना देना।

(क) सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के बारे में कार्यक्रम या योजना बनाना।

(ख) निर्णय, मार्गदर्शन अथवा अनुदेश जारी करना जो सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए लक्षित हो।

(ग) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के उपाय।

(घ) किसी विधि के उपबंधों का सफाई कर्मचारियों पर लागू करना तथा ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ उठाना।

(ङ) सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले में केंद्र तथा राज्य सरकारों को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों या निर्योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाय।

(च) अन्य कोई मामला जो इसके पास केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाए। अपने कार्यों के पालन करने में आयोग को किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से किसी मामले के बारे में सूचना मांगने का अधिकार होगा। आयोग को सौंपे गए कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूरे होने हैं।

**Irregularities by Central Wakf Council**

3431. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether CAG in his report for 1992-93.has pointed out irregularities committed by.the Central Wakf Council for not refunding the unspent balance of grants-in-aid to Government;

(b) if so, whether Government have now got back the unspent grants-in-aid from the council;

(c) if not, action taken thereon; and

(d) whether there is any difference of opinion between CAG and Government in this regard and if so, the steps taken to resolve this impasse?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (d). The Report of the CAG for 1992-93 has not been received in this Ministry as yet. However, it is gathered that the CAG-has, in his report for the year 1992- 93, objected to the retention by the Council of certain amounts which, according to them, had remained unutilised and had wrongly been credited to the wakf fund of the Council. The Council's contention in this regard is that once the amount of grant-in-aid is released by the Government to the Council and the amount is advanced to the wakf institutions / wakf boards for the development of urban wakf properties, the amount of grant-in-aid stands utilised and money received, as refund / repayment of loans, forms part of the Wakf Fund.

Government had earlier drawn the attention of the CAG in this regard to Sec. 8 B(2) and (3) of the Wafk Act, 1954 which read as under:

"8.B(2): All monies received by the Council under Sub-Section (1) and all other monies received by it as donations, benefactions and grants shall form a fund to be called the Central Wakf Fund. 8.B(3): Subject to any rules that may be made by the Central Government in this behalf, the Central Wakf Fund shall be under the control of the Council and may be applied for such purposes as the Council may deem fit."

In view of this, Government had taken the view that the refund of such amounts from the Council may not be insisted upon. Further action will be taken after the report of the CAG is received in this Ministry.

**Child Beggars / Juvenile homes in various states**

3432. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state: